

5.00 P.M.

Clause 5 was added to the Bill.

Clause 1 - Short title and commencement

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): There is one amendment by Shri Kapil Sibal.

SHRI KAPIL SIBAL: I move:

2. That at page 1, line 3, *for the figure "2010" the figure "2011" be substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P. J. KURIEN): There is one amendment by Shri Kapil Sibal.

SHRI KAPIL SIBAL: I move:

That at page 1, line 1, *for the word "Sixty-first", the word "Sixty-second" be substituted.*

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I move:

That the Bill, as amended, be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I thank every Member for his cooperation. It is exactly 5 o'clock.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

**Points arising out of the answer given in the Rajya Sabha on 12th August, 2011,
to Starred Question No. 183 regarding 'Development of higher and technical education in
underdeveloped states'**

श्री राजीव प्रताप रूडी (बिहार): सर, तारांकित प्रश्न संख्या 183 जो राज्य सभा में 12 अगस्त, 2011 को उठाया गया था और जिसका जवाब माननीय मंत्री कपिल सिब्बल साहब द्वारा दिया गया था। आपने जिस संदर्भ में उत्तर दिया था, उससे हम काफी सदस्य उद्देलित हो गए थे। इसका विषय था कि "अल्प-विकसित राज्यों में उच्च

और तकनीकी शिक्षा का विकास" किस प्रकार से पूरे देश में हुआ। महोदय, जो उत्तर था, उसमें दो-तीन उद्देश्य दिए गए थे और वैसे भी आपकी अंग्रेजी अच्छी है, तो आपके विभाग की भी अंग्रेजी अच्छी होगी और आपने उसमें बड़े स्पष्ट तौर से कहा था, you have given very good answers in the reply to the question. जो सरकार में औसतन उपयोग होता है, वह आपने भी किया था, यह कोई नयी बात नहीं है। लेकिन आपने कहा था, "the intent of the Government is to have an inclusive...", "there should be equality", "there should be an equitable situation", and "the Universities being established or the education centres being established should be accessible". अगर इसको हिन्दी में परिवर्तित करें, तो समग्रता हो, जब भी कहीं नयी संस्था बनायी जा रही हो, तो उसमें समग्रता हो, उसमें गुणवत्ता हो, उसमें जो हम निर्णय लें, वह समाज के लिए न्यायसंगत हो और सुगम हो। यह आपने उसमें पहली बार लाइन में उत्तर दिया। अगर आप अपना उत्तर देखें, तो उसमें आपने लिखा है कि, "Government has taken several initiatives for the development of under-provided areas". This was the gist of the beginning of your reply. और उसमें तो सामान्य रूप से हमारे बिहार के सदस्य ने पूछा कि आप केन्द्रीय विश्व विद्यालय बना रहे हैं, बिहार में भी बनाने का प्रस्ताव है? आपने 16 केन्द्रीय विश्व विद्यालय स्वीकृत किए हैं, जिसमें झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है और बिहार में भी है। जब यह स्वीकृत हो गया तो आपसे पूछा गया कि इस केन्द्रीय विश्व विद्यालय को बिहार के मुख्य मंत्री, बिहार की जनता चाहती है कि इसको चम्पारन में बनाया जाए। जैसे ही हम लोगों ने इस विषय को उठाया, जो आपका संवाद था, क्षमा कीजिए आप सांसद भी हैं, आप वरिष्ठ वकील भी हैं, पता नहीं आपको देश और दुनिया से कितना सरोकार है, लेकिन दिल्ली से हैं, तो हो सकता है कि दिल्ली के सीमित दायरे में आप कई बार विषय को सोचते हों, ऐसी स्थिति में, आपका उत्तर था कि जिस स्थान पर केन्द्रीय विश्व विद्यालय बनाये जाने का प्रस्ताव है, यह एक दूर-दराज क्षेत्र में है, बिहार के एक कोने में है, वह बहुत दूर है, वहां पर पहुंच नहीं सकते हैं, वहां पर पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, वहां हवाई अड्डा नहीं है, वहां रेल लाइन नहीं है यानी कि देश में जहां पर हवाई अड्डा नहीं होगा, जहां रेल लाइन नहीं होगी, जहां पर सड़क मार्ग से पहुंचने का रास्ता नहीं होगा, तो वहां विद्यालय नहीं होंगे, वहां अस्पताल नहीं होंगे, वहां विश्व विद्यालय नहीं होंगे, सरकार के नये सोचने का तरीका ये है कि ऐसे स्थानों पर जहां सहूलियत नहीं होगी, जहां संरचनात्मक आधार नहीं होगा, वहां पर हम कुछ करना नहीं चाहेंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सदस्य भी हैं, समय-समय पर हवाई अड्डे पर भी जाते हैं, रामलीला ग्राउंड की समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते हैं। मैं तो बता रहा हूं कि आप वरिष्ठ हैं, आप प्रयास करते हैं। मैं सिर्फ आपको एक चीज की जानकारी देना चाहता हूं, पता नहीं शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा, हम तो उसी राज्य से हैं - एक

जगह है जिसका नाम चम्पारण है। इतिहास में जब आप चम्पारण का नाम सुनेंगे, तो चम्पारण से कई चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर आप चम्पारण के इतिहास में जाएंगे, तो पाएंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी उससे जुड़े थे। एक समय में वहां पर नील की खेती होती थी। इस देश में 1912-13 में किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ था। बिहार में भी वह आंदोलन हुआ। उसमें बहुत से किसानों के साथ अत्याचार हुआ। उस समय श्यामाप्रसाद शुक्ल जी स्वतंत्रता संग्राम के सदस्य थे, उन्होंने महात्मा गांधी जी से आग्रह किया कि आप बिहार चलिए, वहां किसानों का एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। उसी समय लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जो मोतिहारी आंदोलन चल रहा है, हमारा उसको समर्थन है, क्योंकि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। उसी संदर्भ में महात्मा गांधी वहां पहुंचे, अंग्रेजों ने उन पर रोक लगाई। उन्होंने सत्याग्रह किया। इस तरह से इस देश में सत्याग्रह की प्रथम शुरुआत उसी आंदोलन से हुई और आज तक इस देश में लोग उसका अनुसरण करते हैं। हो सकता है कि जो विभाग से कपिल सिब्बल साहब की ब्रीफिंग आई थी, उसमें पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण और मोतिहारी की चर्चा नहीं हुई होगी, महात्मा गांधी जी की चर्चा नहीं हुई होगी, हो सकता है, इसलिए उन्होंने वहां हवाई अड्डा, रेलवे लाइन, बस आदि की बात कही हो। महोदय, आप जानते हैं कि जो बिहार का इतिहास है, उसमें 45 वर्ष तक कांग्रेस का लम्बा शासन रहा है। उसके बाद एक दूसरे 15 वर्ष का शासन रहा है। इस तरह से बिहार के 60 वर्ष तो वैसे ही निकल गए। केवल पांच वर्ष ही मिले। हमने इन पांच वर्षों में कई काम प्रारम्भ किए और उस प्रयास में बिहार के मुख्य मंत्री ने यह भी कहा कि हमारे यहां एक विश्वविद्यालय की जरूरत है, क्योंकि चम्पारण और मोतिहारी के लोगों ने इसकी मांग की है। आपने यह कहा कि वहां पर विश्वविद्यालय संभव नहीं है। हो सकता है, बिहार के मुख्य मंत्री ने आपको हिन्दी में पत्र लिखा हो, कई बार भारत सरकार पर हिन्दी में पत्र लिखने का प्रभाव नहीं होता है। हम अगली बार बिहार के मुख्य मंत्री से आग्रह करेंगे कि जब भी आप प्रभावशाली ढंग से लिखना चाहें, तो कम से कम कपिल सिब्बल साहब को जब इन विषयों के बारे में कहें, तो आप पत्र अंग्रेजी में लिखें। जो परम्परा बन रही है, उसमें अंग्रेजी से कुछ ज्यादा काम निकल सकता है, ऐसा लगता है कि हिन्दी में पत्र लिखने से कम काम निकलता है। इस विषय पर बिहार के मुख्य मंत्री ने कितने ही पत्र लिखे हैं। वैसे में अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद ही अच्छी अंग्रेजी बोल लेता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रभाव की दृष्टि से, आपके दृष्टिकोण से बेहतर होगा। अगर भारत सरकार से आग्रह करना हो, तो हिन्दी में पत्र न लिखें, ऐसा मुझे लगने लगा है। यह सत्य नहीं हो सकता है, मैं मानने के लिए भी तैयार नहीं हूं।

महोदय, इसके अलावा एक मामला और भी है। हम कहते हैं कि पूरे देश में विकास का काम है। There is something called constitutional propriety. राज्य सरकारों से बार-बार चर्चा होती है कि साहब, राज्य सरकारों पर केन्द्र सरकार दबाव डालती है कि आपको ऐसे ही काम करना होगा। सब राज्य सरकारें बार-बार यही कहती हैं

कि यह तरीका ठीक नहीं है। आप हमें स्वायत्तता दीजिए। उस स्वायत्तता के बारे में हमेशा That fine fabric of relationship between the Centre and State is always discussed. आप यहां बैठकर तय करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या मोतिहारी के लोगों का अधिकार नहीं है कि वहां पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय बने। आप जिस अधिकार से कहना चाहते हैं, हमारी यह सोच है कि आपने जो आधार बनाया है और यदि मैं मामले को आगे लेकर बढ़ूं, तो जो संविधान का 7th शैड्यूल है, इसमें Education is under the Concurrent List. We agree to that. आपका भी उसमें अधिकार है। आप कहेंगे कि केन्द्र सरकार का अधिकार है, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं। केवल पैसा देने के अधिकार पर आप किसी राज्य सरकार को उसकी इच्छा से वंचित कर देंगे, तो यह कहां तक सत्य है, मैं यह जानना चाहूंगा? अगर आपको लगता है कि मोतिहारी बहुत ही पिछड़ा इलाका है, तो अब बिहार राज्य बहुत पिछड़ा राज्य नहीं रह गया है। पांच सालों में वहां पर सड़कों का निर्माण हो चुका है, काफी विकास हो चुका है। वहां पर अच्छी स्थिति बनी है, इसलिए आप अपनी सोच में थोड़ा परिवर्तन करिए। ...**(व्यवधान)**... देखिए, अगर उस राज्य को देश के प्रधान मंत्री विशेष दर्जा नहीं दे रहे हों, तो उसके अलग-अलग कारण हो सकते हैं। मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। ...**(व्यवधान)**... जब आप मंत्री बनें, तब जवाब दे दीजिए। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): रूडी जी, आप दो-तीन मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी: मुझे स्मरण कराना पड़ेगा कि जैसे नेहरू जी के समय में, there was a concept of mixed economy, आप देखेंगे कि देश भर में बड़े-बड़े उद्योग बिटाए गए। बोकारो में, जिस समय कुछ नहीं था, वहां बोकारो स्टील सिटी बनी, मिलाई स्टील प्लांट बना, दुर्गापुर बना, इस प्रकार से देश में एक सोच थी कि जहां विकास नहीं है, वहां विकास पहुंचाने के लिए केंद्र की संस्थाओं को भेजा जाता था, ताकि विकास हो सके, लेकिन आज केंद्र सरकार ने नजरिए में एक बिल्कुल परिवर्तन है, ऐसा नजरिया है कि साहब, जो पिछड़ा इलाका है, उसको हम पिछड़ा रखेंगे। हमारा यह सुझाव है कि दिल्ली को पेरिस बनाने का विचार तब तक मत कीजिए, जब तक पूरा देश फ्रांस नहीं हो जाए। आप एक जगह को बनाना चाहते हैं, ...**(व्यवधान)**.. मैं इटली की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपका जो विचार है, आपके सोचने का जो तरीका है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। बिहार के लोग चाहेंगे, हम सब लोग चाहेंगे कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय की जो बात कही गई है, उसमें न्याय हो। सर, आप सहमत हैं? ...**(व्यवधान)**... सर, आप भी सहमत लग रहे हैं। बिहार में जो केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की बात है, उसे निश्चित तौर से मोतीहारी में ही बनाया जाए। मैंने आपको इतिहास के कुछ संदर्भ दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, अगर आपके विभाग के लोग थोड़ा अध्ययन करें और बिहार के प्रति आपकी संवेदना हो, वैसे भी आप कभी बिहार से राज्य सभा के सदस्य रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): रूडी जी, समाप्त कीजिए।

श्री राजीव प्रताप रूडी: इस पूरे विषय पर विचार करते समय बिहार में...(व्यवधान)... माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है, वह मोतीहारी में की जाए। मेरा यह आग्रह है कि पूरा उत्तर बिहार आपका आभारी रहेगा, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी धन्यवाद। उस दिन 12 तारीख को, जब माननीय मंत्री जी ने तारांकित प्रश्न 183 का जवाब दिया था, खास तौर से हम उत्तर प्रदेश के लोग, क्योंकि पूर्ण रूप से उपेक्षित उस प्रश्न के जवाब में उत्तर प्रदेश था, मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि उत्तर भारत को एक तरीके से जान-बूझकर, सुनियोजित तरीके से यह सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर कर रही है। क्योंकि राजनैतिक यश से मजबूत हम उत्तर भारत के लोग, खास तौर पर उत्तर प्रदेश, जहां से लोक सभा के अस्सी सदस्य आते हैं, वहां हमें जान-बूझकर शिक्षा के क्षेत्र में इग्नोर किया जा रहा है, हम इस पर उत्तेजित हुए और हम लोगों ने नोटिस दिया कि इस पर आधे घंटे की चर्चा दी जाए, आपने allow किया, तो उसी के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह बात सही है, जैसे हमारे भाई रूडी जी कह रहे थे कि आप दिल्ली को पेरिस बना लें, लेकिन जब तक आप हिंदुस्तान को शिक्षित नहीं बनाएंगे, दिल्ली कभी उसके बीच चमकेगी नहीं, कभी दिखाई नहीं देगी। श्रीमन्, उत्तर प्रदेश 21 करोड़ की आबादी का है। अगर देश होता तो शायद विश्व के किसी देश की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का भी नंबर आता। वहां पर एजुकेशन की क्या स्थिति है? आप हायर एजुकेशन देख लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पर दो पुरानी यूनिवर्सिटीज, एक बनारस, एक अलीगढ़ हैं। बाद में एन.डी.ए. गवर्नमेंट के समय में इलाहाबाद को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। 21 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश में मात्र तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। एक आई.आई.टी. कानपुर, एक आई.आई.एम. लखनऊ है। जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान थे, वे आपने एक भी उत्तर प्रदेश में नहीं दिए। आखिर क्यों? इसका कारण क्या है, क्या आप बताएंगे? केंद्रीय विद्यालय की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में मात्र 102 केंद्रीय विद्यालय हैं। श्रीमन्, जवाहर नवोदय विद्यालय, 70 हैं। क्या इतने से संस्थानों से आप उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ जनता को हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन देंगे? आप संतुष्ट करना कहते हैं, कैसे संतुष्ट होगा? हम आरोप लगा रहे हैं, हम उत्तेजित हैं। आप देख लीजिए, मैं उत्तर भारत के सिर्फ पांच राज्य दूंगा। बिहार में शिक्षा का प्रतिशत प्राइमरी का मेल, फीमेल का 59.68 प्रतिशत और 33.12 प्रतिशत है, यह 2005 की सेंसेस के हिसाब से है, झारखंड में 66 प्रतिशत और 38 प्रतिशत है, मध्य प्रदेश में 76 प्रतिशत और 50 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश में 68 प्रतिशत और 42 प्रतिशत है, वेस्ट बंगाल में 77 प्रतिशत और 59 प्रतिशत है। ये पांच स्टेट, जो देश की सरकार बनाते हैं, उन पांच स्टेट्स में शिक्षा की स्थिति क्या है? मंत्री जी, मैं आपसे इसका जवाब चाहूंगा। आप "एजुकेशन टू ऑल" बिल लाए, लेकिन आपने राज्य सरकार से

कोई चर्चा नहीं की कि फाइनेंस की क्या स्थिति होगी, हम कहाँ से वित्तीय सहायता देंगे। आपने राज्य सरकारों को लिख दिया कि पचास-पचास प्रतिशत अंशदान आपका होगा। मुझे जानकारी है कि अधिकांश राज्यों ने इसका विरोध किया। हमारे उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने आपको कम-से-कम तीन विट्टियाँ लिखीं। उन्होंने विट्टी हिन्दी में लिखी है, हो सकता है आप न पढ़ पाए हों, हम उन्हें इंग्लिश में translate कर देंगे। आज तक वित्तीय प्रबन्धन न होने के कारण आप जिस "Education to all" की बात कर रहे हैं, वह कहीं लागू नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश ने यह कहा कि आप 90 परसेंट bear कीजिए, 10 परसेंट हम bear करेंगे, क्योंकि छठा वेतन आयोग लागू होने के बाद वैसे भी राज्यों की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, आज तक आपने इसका जवाब नहीं दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपसे 3 साल के लिए 22,868 करोड़ रुपए माँगे। माननीय मंत्री जी, मैं आज आपसे जवाब चाहूँगा कि यूपीए ने दो चीजें बड़े जोर-शोर से घोषित की थीं - "Education to All" and "Food to All". मुझे तो आज तक न "Education to All" दिखाई दे रहा है, न "Food to All". अब आप ऐसी ही फर्जी घोषणाएं करेंगे, तो रामलीला मैदान रोज भरेगा ही। रामलीला मैदान कैसे खाली होगा? आप जो घोषणा करिए, उसका पालन करिए। अगर नहीं किया, तो वैसे भी जनता में आपकी साख खत्म हो गई है, आगे साख लौटने वाली नहीं है। आप यह गलतफहमी न रखिए कि आप 5 साल के लिए सरकार चला लेंगे, तो आप देश में बहुत बड़ा झंडा गाड़ देंगे। जब सरकार की साख जनता में होगी, तभी झंडा गड़ेगा।

श्रीमन्, मैं आपके सामने एक बात लाना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र सरकार की क्या योजना है, higher education में केन्द्र की क्या योजना है? मैं यह कहूँगा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आप निजी क्षेत्र को कौन-सी प्राथमिकता दे रहे हैं? आज निजी क्षेत्र की बढ़ावा केवल उत्तर प्रदेश में करीब 300 इंजीनियरिंग कॉलेजें हो गए। किसी जमाने में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग इंजीनियर बनने के लिए कर्नाटक, मुम्बई, वगैरह जाते थे, आज उत्तर प्रदेश में खुद निजी क्षेत्र ने इसकी व्यवस्था कर दी है। लेकिन जब तक आप उनको facilities नहीं देंगे, जब तक आप उनको कोई सहायता नहीं देंगे, जब तक आप कोई नीति नहीं बनाएंगे, जब तक आप स्पष्ट विचारधारा नहीं रखेंगे, तब तक आप जो "Education to All" कहते हैं, आप सबको वह शिक्षा दे पाएंगे, इस पर हमें शंका है। पिछले मानव संसाधन मंत्री देश में तमाम डीम्ड यूनिवर्सिटीज खोल गए थे, आपने आकर सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज cancel कर दीं। छात्रों ने विरोध किया और जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, तो आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज को रोकना पड़ा। मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूँ कि आज उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग डीम्ड यूनिवर्सिटीज चाहते हैं। मैं अपनी मुख्य मंत्री जी को बधाई दूँगा कि उन्होंने कम-से-कम उत्तर प्रदेश में तमाम स्टेट यूनिवर्सिटीज तो दीं। **...(समय की घंटी)...** लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटी पर भी अपनी पॉलिसी की घोषणा करें। आप केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को रख कर उसी पर चलने लगे, तो यह ठीक नहीं है। जब तक आप कोई स्पष्ट नीति नहीं तय करेंगे, तब तक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार होगा या नहीं, इस पर हमें शंका है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): अग्रवाल जी, आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: आप बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, आप Lawyer हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं, मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जितनी सरलता लाएंगे, जितनी easiness लाएंगे, कानून को जितना व्यावहारिक करेंगे, शिक्षा का क्षेत्र उतना बढ़ेगा। जब तक देश शिक्षित नहीं होगा, माननीय मंत्री जी, मुझे शंका है कि देश के विकास के ऊपर कि यह विकसित होगा या नहीं। **...(समय की घंटी)...**

श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं चाहूंगा कि विन्ता हम सबकी है, हम सब चाहते हैं कि education 100 परसेंट होनी चाहिए, सबकी इच्छा है कि देश शिक्षित हो, आप आज कम-से-कम यह घोषणा करें, स्पष्ट करें कि कौन सी नीति है और "Education to All" में finance के बारे में आपका क्या विचार है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Now, the Minister will reply. **...(Interruptions)...** I will give you the opportunity. After the reply of the Minister, you can speak clarifications. There are three or four Members who want to seek clarifications. But everything should be over in half-an-hour.

मानव संसाधन विकास मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके सामने एक कन्फेशन करना चाहता हूँ। मैं खुलेआम यह कह सकता हूँ कि न तो मुझे ज्यादा अच्छी हिन्दी आती है और न ही ज्यादा अच्छी अंग्रेजी आती है। राजीव प्रताप रूडी जी, मैं मानता हूँ कि आप अंग्रेजी भी मुझसे ज्यादा अच्छी जानते हैं और हिन्दी भी। मैं यह भी मानकर चलता हूँ कि मुझे इतिहास का भी कुछ पता नहीं है, हालांकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाता था, लेकिन मैं यह मानकर चलता हूँ कि आपको इतिहास ज्यादा पता है और मुझे कम पता है। जहाँ तक रही बात सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की **...(व्यवधान)...**

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, only ten minutes are left. I know, there are three-four clarifications too. **...(Interruptions)...** You reply in four minutes.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, I will reply in four minutes.

श्री राजीव प्रताप रूडी: मेरे शब्दों से अगर आपको चोट लगी हो तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ।

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, we are extremely concerned. It is our endeavour to cooperate with all the State Governments, especially Uttar Pradesh and Bihar because, I think, these are two States which need enormous investments in the field of education. Of course, there are other States also

like the State in the north-east, Uttarakhand, Rajasthan. All of these States need enormous investment in education.

बिहार के मुख्य मंत्री के साथ हम इसके लिए चेष्टा करते रहे हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये कुछ विट्टियां हैं, जो हमारे मंत्रालय ने मुख्य मंत्री जी व बिहार सरकार को लिखी हैं। इसके लिए मैंने उनसे आग्रह किया था, आग्रह इसलिए नहीं कि हम पैसा देते हैं और हम ही यह तय करेंगे कि केन्द्रीय यूनिवर्सिटी कहां होनी चाहिए, लेकिन आग्रह इसलिए किया गया था कि सबसे महत्वपूर्ण बात बिहार के बच्चों की है। बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उच्च स्तर की शिक्षा मिले, अच्छे फैकल्टी के लोग नियुक्त हों, अच्छा इन्फ्रास्ट्रक्चर मिले।...(व्यवधान)...

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: क्या आप सिर्फ बिहार की बात करेंगे, यूपी के बारे में भी बताइए।

श्री कपिल सिब्बल: दो मिनट, बिहार की बात करके मैं तुरन्त यूपी की बात ही करूंगा।

वाइस चांसलर ने हमें विट्टी लिखी है कि मोतिहारी में जो जगह है, वह सही नहीं है इसलिए यहां पर यूनिवर्सिटी नहीं बन सकती। इसके बाद मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा, जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, आप ही इसका कुछ करिए। इसके बाद मैंने वहां पर एक इंसपेक्शन टीम भेजी। वह इंसपेक्शन टीम वहां गई और उन्होंने भी हमें यही सुझाव दिया कि मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। इसके बाद फिर मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा और कहा कि अगर यहां नहीं हो सकती, तो पटना में सोचिए, पटना में नहीं हो सकती, तो गया में सोचिए, गया में नहीं हो सकती, तो नालंदा में सोचिए अथवा किसी और जगह सोचिए, ताकि हम आपके साथ चल सकें। उन्होंने उत्तर दिया कि नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी तो मोतिहारी में, नहीं तो कहीं नहीं बनेगी। मैं आज भी आग्रह करता हूं...(व्यवधान).... जहां तक चम्पारण का सवाल है, हम मानते हैं कि इतिहास में वह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। मैंने उनको विट्टी में लिखा भी है कि अगर ऐसी ही बात है तो आप एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनाइए, चूंकि हमारी एक स्कीम है, उसके तहत हम स्टेट यूनिवर्सिटी बनवाने में आपकी पूरी मदद करेंगे, चम्पारण में एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनवा देंगे, लेकिन जहां तक केन्द्रीय यूनिवर्सिटी का सवाल है, हमें बिहार के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। आप और हम इकट्ठे साथ-साथ चलेंगे, तभी हम ऐसा कर पाएंगे।

जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में कहीं पर सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, तो वे उत्तर प्रदेश में हैं। चार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में ही हैं, फिर चार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज दिल्ली में हैं, तीन आन्ध्र प्रदेश में हैं, दो असम में हैं और बाकी स्टेट्स में केवल एक-एक है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: मेरी एक आपत्ति है, 21 करोड़ की आबादी पर केवल चार यूनिवर्सिटीज हैं।...(व्यवधान)...

श्री कपिल सिब्बल: एक मिनट, एक मिनट ...(व्यवधान)... अगर मैं आपको आंकड़े बताने लगा तो बहुत समय लग जाएगा, लिखित में मैं आपको दे दूंगा। शिक्षा के सम्बन्ध में जितना पैसा हम उत्तर प्रदेश में खर्च करते हैं, शायद ही किसी और राज्य में खर्च करते हों। आंकड़े देकर मैं आपको यह बता सकता हूँ। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको बताऊँ कि 2010-11 में केवल उत्तर प्रदेश की चार यूनिवर्सिटीज़ में ही 65,355 स्टुडेंट्स एनरोल्ड हुए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की टोटल एनरोलमेंट 1,78,000 थी। इनमें काफी संख्या में स्टुडेंट्स दिल्ली में हैं। 39% of all enrolment in India in Central Universities is in only Uttar Pradesh, which only shows that this Government is going as much as it can. आपको आईआईएम भी मिला है, आपको आईआईटी भी मिला है। सर, इन्हीं के भी तीन रीजनल सेंटर्स बनारस, लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में खुले हैं ...(व्यवधान)... हम कभी उत्तर प्रदेश से भेदभाव नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Mr. Minister, there are two more questions. After that, you can answer. Only five minutes are remaining and only two-three questions more. Now, just a question...

डा. अखिलेश दास गुप्ता (उत्तर प्रदेश): सर, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में चार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी डा. बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, लखनऊ में है। माननीय मंत्री जी बहुत ज्ञानी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को उस यूनिवर्सिटी में आमंत्रित करना चाहता हूँ। वे जाकर देखें कि उस Central University का क्या हाल है। क्या उसका नाम बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? उस Central University का हाल यह है कि भारत सरकार के द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहाँ professors की कमी है, teachers की कमी है, facilities नहीं हैं, ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): श्री रामविलास पासवान।

डा. अखिलेश दास गुप्ता: मैं जानता हूँ। ...(व्यवधान)... मैं यह बात आपकी जानकारी में लाया हूँ। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): अब टाइम नहीं है। ...(व्यवधान)... आपको रिप्लाय नहीं मिलेगी। ...(व्यवधान)...

डा. अखिलेश दास गुप्ता: मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे। ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay, please.

डा. अखिलेश दास गुप्ता: मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप कृपया वहाँ आकर देखें ...(व्यवधान)... हम आपका स्वागत करेंगे।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): अब आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... Okay, Guptaji, हो गया। Now, Paswanji, just a question. ...**(व्यवधान)**... आप प्रश्न पूछिए।

श्री रामविलास पासवान (बिहार): उपसभाध्यक्ष जी, मैं रूडी जी का समर्थन करता हूँ। एक कहावत है कि 'पहले अंडा या पहले मुर्गी'। पहले infrastructure बनेगा या पहले विकास होगा? जब infrastructure बन जाएगा तब विकास automatically हो जाएगा। मैं भी मोतिहारी गया था। मोतिहारी एक बहुत important जगह है। मेरा आपसे आग्रह है कि ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): आप प्रश्न पूछिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: ठीक है, सर। ...**(व्यवधान)**... वह महात्मा गांधी की कर्मभूमि है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): नहीं तो रिप्लाय नहीं मिलेगी। ...**(व्यवधान)**... इस आधे घंटे में कवर होना है।

श्री रामविलास पासवान: मैंने एक Unstarred Question भी पूछा था। ...**(व्यवधान)**... मेरा आपसे आग्रह है कि आप सारे नियमों को शिथिल करके और स्पेशल केस में मोतिहारी में Central University बनाने की व्यवस्था कीजिए। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Okay. Now, Shri Rajniti Prasad.

श्री रामविलास पासवान: सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। मेरी constituency हाजीपुर है, जो वैशाली जिले में है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): अब कहने का टाइम नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

श्री रामविलास पासवान: सर, वैशाली जिला भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह एक ऐतिहासिक जगह है। ...**(समय की घंटी)**... ...**(व्यवधान)**... सर, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो. पी.जे. कुरियन): टाइम नहीं है, इसलिए रिप्लाय नहीं मिलेगी। ...**(व्यवधान)**... आपको रिप्लाय नहीं चाहिए?

श्री रामविलास पासवान: मोतिहारी में इसे खोलने के लिए सरकार विचार करे। ...**(व्यवधान)**... वह फाइल रिजैक्ट मत कीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Rajniti Prasad. Please put your question in only one sentence.

श्री राजनीति प्रसाद (बिहार): सर, मोतिहारी एक ऐतिहासिक जगह है। वहाँ हमें Central University खोलनी चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि कोई और जगह भी है क्या? ...**(व्यवधान)**... एक सेकंड, एक सेकंड ...**(व्यवधान)**... एक जगह और आपके जो ...**(व्यवधान)**... Sir, one

sentence. ...(व्यवधान)... Sir, one sentence. ...(व्यवधान)... तो क्या बिहार सरकार के इस आग्रह को आप मानेंगे कि मोतिहारी में Central University खोली जाए? धन्यवाद।

श्री एन.के. सिंह (बिहार): सर, क्या माननीय मंत्री जी इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि वह कौन-सी ऐसी प्रक्रिया है और कौन-सा ऐसा criteria है, जिसके आधार पर मोतिहारी को reject किया गया है? क्योंकि, जितने प्रश्न मंत्री जी ने उठाये ...(व्यवधान)... उनके जवाब मुख्य मंत्री जी ने पूर्ण रूप से दिये हैं। लेकिन, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है और कौन-सा ऐसा criteria है, जो fulfill नहीं हो रही है और जिसके कारण आप मोतिहारी में Central University के लिए नहीं मान रहे हैं?

श्री आर.सी. सिंह: सर, ...(व्यवधान)...

SHRI MOINUL HASSAN (West Bengal): I just want to put one question.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, you should have given your name earlier. The Minister will reply.

SHRI MOINUL HASSAN: I just want to put one question.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): No, no, it is not possible. There are only two minutes left. Let him reply.

SHRI MOINUL HASSAN: There should be another Central University in West Bengal. It is a big State but there is only one Central University.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, a new Member is deprived.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You should have given your name earlier. Please sit down. You should know the rules also.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: I want to put a question in just one sentence.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): You and all are equal here.

श्री कपिल सिब्बल: सर, अखिलेश जी ने कुछ सवाल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर युनिवर्सिटी के बारे में उठाए हैं। मैं एक बार वहां गया भी हूँ, लेकिन मैं आपके साथ भी जरूर चल पड़ूंगा।

डा. अखिलेश दास गुप्ता: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कपिल सिब्बल: लेकिन, मुझे इतना मालूम है कि अम्बेडकर युनिवर्सिटी में जो enrollment है, वह पिछले तीन सालों में 7% से लेकर 1,39% हुआ है। तो वहां enrollment बहुत बढ़ा है। अम्बेडकर युनिवर्सिटी में जो investment है, वह plan स्कीम के तहत 58 करोड़ और non-plan के तहत 26 करोड़ दिया गया है। यह पैसा

अम्बेडकर युनिवर्सिटी को दिया गया है। फिर भी मैं वहां गया हूं और मैंने खुद देखा है कि वहां नई-नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन मैं आपके साथ वहां जरूर चलूंगा।

जहां तक बिहार का सवाल है, तो हम किसी को इनकार नहीं करते। ...(व्यवधान)... हम क्यों इनकार करेंगे? ...(व्यवधान)... हमारी सोच भी ऐसी नहीं है।

श्री वैष्णव परिडा: सर, ...(व्यवधान)... उड़ीसा के बारे में भी कुछ बताइए ...(व्यवधान)...

श्री कपिल सिब्बल: लेकिन, हमारा जो लक्ष्य है, वह यह है कि बिहार के बच्चों का भविष्य कैसे उज्ज्वल हो। यह हमारा लक्ष्य है। इसी संदर्भ में उनसे बातचीत करके कोई-न-कोई निर्णय जरूर करेंगे।

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): I have to inform Members that the Business Advisory Committee in its meeting held on Thursday, the 25 August, 2011, allotted, time for Government Legislative Business, as follows:-

Business Time Allotted

- | | | |
|-----|--|------------|
| 1. | Consideration and passing of the Copyright (Amendment) Bill, 2010. | Three hrs. |
| 2. | Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by the Lok Sabha:- | |
| (a) | The Customs (Amendment and Validation) Bill, 2011 | Two hrs. |
| (b) | The Academy of Scientific and Innovative Research Bill 2010 | Two hrs. |

The Committee recommended that the sitting of the Rajya Sabha fixed for Thursday, the 1st September, 2011 may be cancelled on account of Ganesh Chaturthi. Accordingly, there will be no sitting of the House on that day.

The Committee also recommended that the House may sit on Saturday, the 27th August, 2011 and 3rd September, 2011 and there will be no Question Hour on those days.

The Committee further recommended that the Private Members' Business (Resolutions) scheduled for Friday, the 26th August, 2011 and the Private Members' Business (Bills) scheduled for Friday, the 2nd September, 2011 may be taken up on Saturday, the 27th August, 2011.